भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3203

20/03/2026 को उत्तरार्थ

विषय- कावेरी और कृष्णा नदी बेसिन में कृषि पर जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन

3203 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में कावेरी और कृष्णा नदी बेसिनों, विशेष रूप से कर्नाटक में, सूखे, भीषण गर्मी और अत्यधिक वर्षा जैसी जलवायु संबंधी कृषि संबंधी जोखिमों का आकलन किया है; और

(ख) जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार फसल खराब होने वाले इन क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, फसल बीमा तंत्र और जिला स्तरीय आकस्मिक योजना में सुधार शामिल हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचर (एनआईसीआरए) नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जिला स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता आकलन का संचालन करती है और जलवायु परिवर्तन के भविष्य के अनुमानों का आकलन करने के लिए इंटीग्रेटेड सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन करती है। इस परियोजना के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार, 651 प्रमुख रूप से कृषि प्रधान जिलों में कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के जोखिम संवेदनशीलता का जिला स्तरीय आकलन किया गया है। कुल 310 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को अति संवेदनशील' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। कर्नाटक में, गडग, हावेरी और चित्रदुर्ग 'अत्यधिक उच्च' जोखिम श्रेणी में आते हैं, जबकि बागलकोट, कलबुर्गी, बीदर, कोप्पल, धारवाड़, बल्लारी, तुमकुरु, कोलार, बेंगलुरु (ग्रामीण), हसन, मैसूरु और चामराजनगर को 'उच्च' जोखिम श्रेणी में रखा गया है। एनआईसीआरए के तहत, लू और सूखे जैसी जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चामराजनगर, चिक्काबल्लापुर, चित्रदुर्ग, गडग, कलबुर्गी, हावेरी और तुमकुरु में स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। एनआईसीआरए मॉडलिंग परियोजनाओं के अनुसार, कावेरी बेसिन में भविष्य में जल प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे चावल और गन्ना प्रभावित होंगे; अनुशंसित कार्यनीतियों में फसल विविधीकरण, अधिक जल खपत वाली फसलों में कमी, जल-बचत प्रौद्योगिकियां और

जलाशय संवर्धन शामिल हैं। कृष्णा बेसिन में, चना और गन्ने की सिंचाई की मांग बढ़ सकती है, रबी ज्वार, अरहर और मक्का की मांग घट सकती है, जबकि चावल की मांग स्थिर रहेगी।

विश्व बैंक समर्थित सुजाला-III परियोजना (2014-19) के तहत, आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी) ने गडग में 12,500 हेक्टेयर, कलबुर्गी में 10,000 हेक्टेयर, रायचूर (कृष्णा बेसिन) में 11,500 हेक्टेयर और चामराजनगर (कावेरी बेसिन) में 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संसाधन सूची (एलआरआई) तैयार की। इसके बाद, वर्ष 2022-25 के दौरान, नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि अनुकूलन के लिए वाटरशेड्स का पुनरूद्धार (आरईडब्लुएआरडी) कार्यक्रम के तहत, कोप्पल और गडग जिलों में विस्तृत एलआरआई किया गया, जिसमें येलबुर्गा में 87 सूक्ष्म वाटरशेड (67,412 हेक्टेयर) और रॉन में 102 सूक्ष्म वाटरशेड (74,762 हेक्टेयर) शामिल थे। मिट्टी की गहराई, बनावट, मिट्टी में कार्बनिक कार्बन (एसओसी), पीएच और पोषक तत्वों की स्थिति से संबंधित खेत-स्तरीय डेटासेट तैयार किए गए और किसानों के लिए 2,16,975 एलआरआई कार्ड बनाए गए। इन डेटासेटों ने भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन, मिट्टी और जल संरक्षण योजना, जल निकासी योजना और जल विज्ञान एटलस के विकास में सहायता प्रदान की है, जिसमें वर्षा, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन (एईटी), अपवाह, मिट्टी की नमी, भूजल और पुनर्भरण की जानकारी शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि और स्थानीय आपदाओं जैसी चरम जलवायु घटनाओं के कारण बुवाई से पहले से लेकर फसलोपरांत तक फसल के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार होने वाले फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को सहायता मिलती है।

इसके अलावा, जलवायु अनुकूलन के लिए किए गए प्रमुख उपायों में जल प्रबंधन (खेतों में तालाब, चैक डैम, मेड़बंदी, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग), फसल अनुकूलता (सूखा-अनुकूल किस्में, अनुकूल अंतर्फसल खेती, बीज को सख्त बनाना) और आजीविका विविधीकरण (घरेलू मुर्गी पालन, उन्नत भेड़ नस्लें, जल-पौधों से उगाया गया चारा, मछली पालन, चारा और साइलेज) शामिल हैं। एनआईसीआरए गांवों में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कर्नाटक राज्य के सभी जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं (डीएसीपी) तैयार की गई हैं।

*****